भाजन



पीवी सिंधू

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए किया क्वालिफाई

गौरवशाली परंपरा का १०७ वर्ष

तब्बू

बचपन से अभिनय की तरफ रहा झुकाव



पटना, गुरुवार, ५ नवम्बर, २०२६ सौर १७ कार्तिक सं. २०८३ वि० | वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, पटना(कोलकाता संस्करण), रांची (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित | ★★ | नगर संस्करण १२ पृष्ठ मूल्य दो रुपये पचास पैसा

नीतीश के सपने को तेजी से पूरा कर रही सरकार : सम्राट

नशे के कारोबार में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत का आरोप, फुलवारी के आठ पुलिसकर्मी निलंबित

फुलवारी शरीफ (आससे)। नशे के कारोबार में पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत का मामला सामने आने के बाद पटना पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ छापेमारी में पकड़े गए दो युवकों को कथित तौर पर 11 लाख रुपये लेकर छोड़ने और पूरे मामले को वरीय अधिकारियों से छिपाने के आरोप में फुलवारीशरीफ थाने के आठ पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

दो युवकों को 11 लाख रुपये लेकर छोड़ने का आरोप

नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) चंद्र प्रकाश के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर फुलवारीशरीफ थाना पुलिस ने नया टोला पठान टोली में छापेमारी की थी. इस दौरान आकिब खान उर्फ मोहम्मद साकिब खान (32) को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 1867/26 के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

जांच के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई कि इसी छापेमारी में मोहम्मद आफताब आलम और मोहम्मद एहसान को भी पुलिस ने पकड़कर थाने लाया था. इसके बावजूद दोनों का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं किया गया. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों से 11 लाख रुपये लेकर उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया. इतना ही नहीं, रुपये के लेन-देन को लेकर पुलिसकर्मियों के बीच आपसी कहासुनी होने की बात भी जांच में सामने आई है.

मामले की प्रारंभिक जांच में आठ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. इनमें सब इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद, नारद मुनि सिंह, रितेश कुमार, आकाश कुमार, पवन कुमार, साबिर आलम, आनंद राज और शुभम कुमार शामिल हैं. सभी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

(शेष पृष्ठ ९ पर)

छठ-दिवाली पर बिहार आने वालों के लिए चलेंगी ज्यादा ट्रेनें
बिहार को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए गाद नीति पर काम

पटना (आससे)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो सपने देखे थे और जिन मुद्दों को लगातार उठाया था, उन्हें अब पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है।



मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात के बाद बिहार के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। इसमें नदियों से गाद निकालकर बाढ़ की समस्या कम करने, छठ-दिवाली पर बिहार आने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने और निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में गाद नीति का निर्माण किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत नदियों से गाद निकालने का काम किया जाएगा। सम्राट चौधरी का कहना है कि इससे बिहार को हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कामों और

(शेष पृष्ठ ९ पर)

इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से मांगी मदद

सम्राट चौधरी ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि बिहार में बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जल्द पर्यावरणीय मंजूरी देने का आग्रह किया गया है.

इसके अलावा राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की मांग भी रखी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में इको टूरिज्म के क्षेत्र में काम हो रहा है. बिहार में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए. इससे पर्यटन के नए केंद्र विकसित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. केंद्र सरकार के सहयोग से उद्योग, परिवहन, पर्यटन और बाढ़ प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है.

नीतीश से मिलने पहुंचे सम्राट
दिल्ली दौरे को लेकर दी जानकारी

पटना (आससे)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौट आये हैं. पटना पहुंचते ही उन्होंने



पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई. मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने बताया कि वह नीतीश कुमार को बधाई देने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई दी गई है. इस दौरान सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात और बिहार के लिए रखे गए प्रस्तावों की भी जानकारी

(शेष पृष्ठ ९ पर)

केंद्रीय कैबिनेट में अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का फैसला

75% की आर्मी में होगी भर्ती, 2 साल का सेवा विस्तार

नयी दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई. इस दौरान कई फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें अग्निवीरों को लेकर खास ऐलान किया गया है. पहले सिर्फ 25 फीसदी सेना में जाने का प्रावधान. हालांकि, अब ये आंकड़ा बड़ा कर 75 फीसदी कर दिया गया, वो भी 2 साल के लिए इसके बाद सभी 75 फीसदी लोगों का चुनाव सेना के पैमाने के तहत ही किया जाएगा.

2 साल पूरा होने के बाद 75 फीसदी अग्निवीर सेना में आ पाएंगे. इस दौरान उन्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे. बता दें कि अग्निवीर का पहला बैच का 4 साल खत्म होने वाला है. केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के अलावा ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज को भी मंजूरी दी



है. कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर फैसला किया, जहां क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग की जाएगी.

कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बुधवार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सबसे पहले, मैं हमारे %क्लीन एनर्जी मिशन% से जुड़े एक बड़े फैसले के बारे में बताना चाहूंगा. भारत ने इस क्षेत्र में अपने प्रदर्शन से नए मानक स्थापित किए हैं और दुनिया भर में पहचान बनाई है. आज कैबिनेट ने 92 जीडब्ल्यूएच की ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज योजना को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने और उनके विस्तार को मंजूरी दी है. इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है. उन्होंने कहा कि इसकी मदद से बच्चों के शोषण और बलात्कार के मामलों से निपटा जा सके. हमारी सरकार का पक्का संकल्प है. समाज में जब भी इस तरह की समस्याएं या खतरे सामने आएं चाहे वह महिलाओं के खिलाफ

(शेष पृष्ठ ९ पर)

शिक्षक-कर्मियों को छठ के पहले मिलेगा लंबित वेतन

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षक-कर्मियों को लंबित वेतन का भुगतान छठ से पहले होगा।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छठ पर्व से पहले लिपिक, परिचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, शारीरिक शिक्षक, संस्कृत और मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने हिदायत दी है कि वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिये। इस बीच दीपावली एवं छठ के मद्देनजर शिक्षकों को शीघ्र वेतन देने की मांग नवनियुक्त माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से की है। इसके लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. गणेश शंकर पाण्डेय ने शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से आग्रह किया है।

मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त
कागज की बोरियों से भरे ट्रक में छिपाकर हो रही थी तस्करी

मुजफ्फरपुर (आससे)। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिवाली से पहले शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बेला फेज-2 स्थित नारायणपुर इंडस्ट्रियल एरिया रोड से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से करीब 1200 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। जिस ट्रक से शराब की खेप मुजफ्फरपुर आ रही थी वो पंजाब नंबर का है। भारी मात्रा में बरामद शराब की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की नजरों से बचने के लिए



तस्करी का नया तरीका अपनाया था। ट्रक के ऊपर कागज और कॉटन के टुकड़ों से भरी बोरियां रखी गई थीं, जबकि नीचे शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे। तस्करों को उम्मीद थी कि इस तरीके से शराब की खेप आसानी से अपने ठिकाने तक पहुंच जाएगी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।

जानकारी के अनुसार, उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब नंबर के एक ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर लाई

(शेष पृष्ठ ९ पर)

50 संस्कृत स्कूल बनेंगे मॉडल

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

- छह विद्यालयों में खुलेगा अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब
- संस्कृत शिक्षा बोर्ड का केंद्रीय भंडारण निगम से करार

पटना। राज्य में 50 संस्कृत स्कूल मॉडल बनेंगे। छह संस्कृत स्कूलों में अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब खुलेगा।

छह संस्कृत स्कूलों में अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब की स्थापना के लिए बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के बीच बुधवार को करार (एमओयू) हुआ है। इस पर नयी दिल्ली में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा एवं केंद्रीय भंडारण निगम के मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक प्रकाश चंद्र राय ने हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर निगम के सीएसआर से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके तहत छह चयनित संस्कृत विद्यालयों में कॉर्पोरेट

(शेष पृष्ठ ९ पर)

यहां भी पढ़ें

website :-
www.ajhindidaily.com
For e-Paper
www.ajhindidaily.com
नि:शुल्क ई-पेपर सब्सक्राइब करें

एमएलसी चुनाव में हार के बाद जदयू ने बुलायी बैठक

पटना (आससे)। बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने जनता दल यूनाइटेड की चिंता बढ़ा दी है. चार सीटों पर हुए चुनाव में पार्टी को तीन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. सिर्फ पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार जीत दर्ज कर सके. अब इन नतीजों के बाद पार्टी नेतृत्व ने हार के कारणों की पड़ताल करने का फैसला किया है. इसके लिए गुरुवार, 5 नवंबर को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई है. बैठक में पार्टी के बड़े नेता, चुनाव जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के साथ संबंधित जिलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे.

जेडीयू की इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

(शेष पृष्ठ ९ पर)

पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के कई ठिकानों पर एसवीयू की रेड
10 लाख रुपये कैश बरामद, पटना-सहरसा तक दबिश

पटना (आससे)। बिहार में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने आय से अधिक संपत्ति के



मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसवीयू की टीम सहरसा में तैनात पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, अधीक्षण अभियंता विजय कुमार के सहरसा स्थित कार्यालय और आवास के अलावा पटना के दानापुर स्थित गोला रोड और महेश नगर में भी एसवीयू की टीम तलाशी ले रही है। इसके साथ ही अभियंता के गृह जिले औरंगाबाद के दाउदनगर स्थित परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है।

विशेष निगरानी इकाई की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की जा रही है। एसवीयू की अलग-अलग टीमें एक साथ सभी चिह्नित ठिकानों पर दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं।

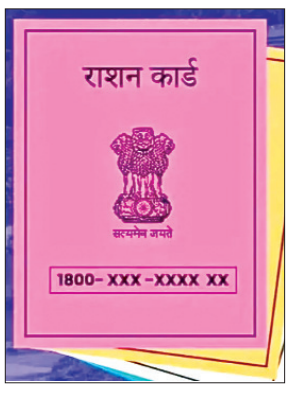
छापेमारी के दौरान अब तक करीब 10 लाख रुपये नकद बरामद होने की सूचना है। फिलहाल

(शेष पृष्ठ ९ पर)



60000 पीडीएस दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार

पटना (आससे)। बिहार में राशन वितरण को लेकर सरकार नई व्यवस्था अपनाने जा रही है. सरकार अब इस काम के लिए एआई की मदद लेगी. राज्य के लगभग 60 हजार पीडीएस दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है. इन दुकानों को डिजिटल निगरानी व्यवस्था से जोड़े जाने की प्लानिंग है. इसके लिए फेयर प्राइस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जाने की खबर है.



मिली जानकारी के अनुसार, नई व्यवस्था से खास फायदा हो सकेगा. इससे यह पता चल सकेगा कि पीडीएस दुकानों में कितना राशन आया, कितना बांटा गया और स्टॉक में कितना राशन बचा हुआ है. इन सभी चीजों पर नजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग की मदद से नजर रखी जाएगी. किसी भी राशन कार्ड को रद्द करने से पहले सत्यापन और प्रक्रिया का पालन जरूर ही किया जाएगा.

बताया जा रहा है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे इस नई व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू कराएं. खबर यह भी है कि बिहार के अलग-अलग जिलों में खोले जा रहे नये 4910 दुकानों को भी डिजिटल व्यवस्था से जोड़ी जाए. विभाग की तरफ से दुकानों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. बिहार के पीडीएस दुकानों को लेकर सरकार की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड, राशन वितरण के दौरान गड़बड़ी और कालाबाजारी को रोकना है. बिहार सरकार की इस नई व्यवस्था को वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत भी कारगर माना

(शेष पृष्ठ ९ पर)

दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों की प्रासंगिकता खत्म : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली (एजेंसी)। भारत में दो से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम की है. अदालत ने कहा है कि देश में लगातार गिरती प्रजनन दर और बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कानूनों ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है. इन कानूनों के पीछे मुख्य आधार बढ़ती आबादी और जनसंख्या विस्फोट का डर था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत की स्थिति बदल गई है. ऐसे में अब इन कानूनों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए 2003 के चर्चित जावेद बनाम हरियाणा राज्य

(शेष पृष्ठ ९ पर)

नौसेना के दो अधिकारियों का होगा कोर्ट मार्शल

नयी दिल्ली (एजेंसी)। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र के पलटने की घटना के करीब दो साल बाद नौसेना ने दो अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस घटना में जहाज के कमांडिंग ऑफिसर (कैप्टन) और ऑफिसर ऑफ द डे (लेफ्टिनेंट कमांडर), दोनों अधिकारियों पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। इसके अलावा कैप्टन पर युद्धपोत को खतरे में डालने का अतिरिक्त आरोप भी लगा है।



21 जुलाई 2024 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में मरम्मत के दौरान भारतीय नौसेना के युद्धपोत ढुह्स ब्रह्मपुत्र में आग लग गई थी। युद्धपोत में लगी इस आग बुझाने के लिए जहाज में बड़ी मात्रा में पानी डाला गया। पानी भरने से युद्धपोत का संतुलन बिगड़ा और वह पोर्ट साइड की ओर झुककर पलट गया। इस पूरे हादसे में लीडिंग सीमैन सितेंद्र सिंह की मौत हो गई।